# अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

- पृष्ठभूमि
- खर्च क्षमता
- पूंजीगत व्यय

# पृष्ठभूमि(1/2)

- कोविड-19 से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
- गरीब और कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को आत्मनिर्भर पैकेज और विस्तार में तरजीह दी गयी है।
- आपूर्ति थोड़ी सामान्य हुई है लेकिन उपभोक्ताओं की मांग अभी भी प्रभावित है.

# पृष्ठभूमि (2/2)

- अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग और उसकी  खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आज कुछ प्रस्ताव पेश किए हैं
  - कुछ प्रस्ताव खर्च क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं
  - अन्य प्रस्तावों को सीधा सम्बन्ध जीडीपी बढाने को लेकर हैं।

## पृष्ठभूमि

## खर्च क्षमता

- **LTC कैश वाउचर स्कीम**
- **विशेष फेस्टिवल एडवांस स्कीम**

## पूंजीगत व्यय

# 1 उपभोक्ता मांग:
# 1/a. LTC कैश वाउचर स्कीम(1/3)

- सरकारी और कई अन्य संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर महामारी का असर नहीं पढा.उनकी तनख्वाह बरकरार रही और बचत बढी।
- **देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना होगा ताकि महामारी से प्रभावित लोगों को इसका फायदा मिल सके।**

LTC कैश वाउचर स्कीम

- प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है.
- कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें कैश वाउचर देने का फैसला किया है. इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा

# एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (3/3)

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

- एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
- राज्य कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा. ऐसे में अगर राज्य सरकारें या प्राइवेट कंपनियां ऐसे ऐलान करती हैं तो उनके कर्मचारियों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.
- इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। यदि आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी।
- एलटीसी वाउचर स्कीम से 28000 करोड़ रुपये की उपभोक्ता मांग बढाने में मदद मिलेगी।

# Consumer demand:
# 1/b. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (1/2)

- 10,000 रुपये के ब्याज रहित एडवांस का भुगतान अधिकतम 10 किस्तों में किया जा सकेगा।
- इस स्कीम के तहत उम्मीद है कि सरकार 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- अगर राज्य सरकार भी इस तरह का एडवांस देती हैं तो 8,000 करोड़ रुपये और खर्च होने की उम्मीद है।इससे 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग सृजित होने की उम्मीद है।

# स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम(2/2)

- इस स्कीम के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारी बिना ब्याज के 10,000 रुपये प्रीपेड RuPay Card के जरिए ले सकते हैं.
- **सरकार इस संम्बन्ध में बैंक खर्च को वहन करेगी.**
- डिजिटल खरीददारी से टैक्स मे बढत और ईमानदार बाजार को बढावा मिलेगा

पृष्ठभूमि ✓

उपभोक्ता खर्च ✓

**पूंजीगत व्यय**

- केंद्र
- राज्य

# 2. पूंजीगत व्यय

- पूंजीगत व्यय
- पूंजीगत व्यय के कई गुना ज्यादा प्रभाव है।
  - यह न केवल वर्तमान जीडीपी बल्कि भविष्य की जीडीपी को भी बढ़ाता है, जिससे कर्ज और अधिक टिकाऊ हो जायेगा।
- राज्यों और केंद्र के पूंजीगत व्यय पर सकारात्मक प्रभाव.

# पूंजीगत व्यय:
# राज्यो के लिए खास सहायता(1/2)

- 12,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण।
- भाग 1: पूर्वोत्तर के लिए 2,500 करोड़ रुपये. उत्तराखंड (1600 करोड़ रुपये) और हिमाचल प्रदेश (900 करोड़ रुपये)
- भाग 2: वित्त आयोग विचलन में हिस्सेदारी के अनुपात में अन्य राज्यों के लिए 7,500 करोड़
  - शुरू में 50%
  - पहली किस्त के उपयोग के बाद शेष राशि
  - अप्रयुक्त धन को फिर से आवंटित किया जाएगा
- भाग 3: राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये जो 4 में से कम से कम 3 सुधारों को आत्मनिर्भर भारत राजकोषीय पैकेज में दिए गए

# पूंजीगत व्यय:
# राज्यो के लिए खास सहायता(2/2)

- नयी और चालू परियोजनाओं के लिए धन और / या ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का निपटान करना.
- 31.3.2021 तक खर्च किया जाना है.
- यह धनराशि राज्यों को दी जाने वाली अन्य अतिरिक्त खर्चो के अलावा होगा
- 50 वर्षों के बाद बुलेट पुनर्भुगतान, तब तक कोई सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है

# 3. केंद्र का पूंजीगत व्यय:
# बजट में बढ़ोतरी का प्रावधान

- सड़कों, रक्षा बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, शहरी विकास, रक्षा बुनियादी ढांचे और घरेलू स्तर पर उत्पादित नेटवर्क उपकरण पर 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा
- आवंटन आने वाले समय मे वित्त और संम्बन्धित मंत्रालयों से विचार विमर्श के बाद किए जायेंगे।

# मांग में तेजी का सार(1/2)

- एलटीसी व त्योहारों के लिए एडवांस से 36,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के लिए 8,000 करोड़ रुपये और एलटीसी वाउचर स्कीम के लिए 28000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- कुल 73,000 करोड़ रुपये की उपभोक्ता मांग पैदा होगी. राशि को 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा।

# मांग में तेजी का सार(2/2)

- एक मोटे अनुमान के मुताबिक निजी क्षेत्र में एलटीसी लाभ की सुविधा से जो उपभोक्ता मांग पैदा होगी वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा की उत्पन्न मांग 28 हजार करोड़ रुपये के बराबर होगी।
- कुल अतिरिक्त मांग 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।
- सरकार के उपाय बाजार में मांग को प्रोत्साहित करेंगे।
- भविष्य की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी
- आज का समाधान कल की समस्या नहीं होना चाहिये।

धन्यवाद